DR. SASMIT PATRA: Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMEE YAJNIK: Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Direct recruitment for the post of Joint Secretary in Central Government

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के बाद सेक्रेटरी और कमिश्नर स्तर पर पहुंचने के बाद सेन्ट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए एम्पैनलमेंट होता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि गवर्नमेंट सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्तियां कर रही है। इससे तीन समस्याएं पैदा हो गई हैं। एक तो आईएएस और आईआरएस की जो पूरी फ्रैटरनिटी है, उसमें नाराज़गी है। दूसरे, लाखों की तादाद में जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनका एक सपना होता है कि वे आईएएस बनें और देश की प्रशासनिक सेवा में जाएं। उनके मन में भी यह आक्रोश है कि हम तो पढ़ते हैं, लिखते हैं, इम्तिहान देते हैं, आईएएस कम्पीट करते हैं, तब आईएएस बनते हैं और ये सीधे बन रहे हैं। तीसरी, इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति यह है कि इन appointments में रिज़र्वेशन का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है।

पहले 9 appointments हुए थे, no SC, no ST, no OBC, तो महोदय, हमारी जो ये परम्पराएं हैं और संस्थाओं की जो इज्ज़त है, उसके साथ खिलवाड़ बंद हो, आप यह निर्देश दीजिए।

मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि डीओपीटी के मंत्री से कहिए कि इस तरह की बातें बंद करें, क्योंकि इससे प्रशासन बेकार हो जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Those who want to associate, please send their slips. जितेन्द्र सिंह जी नहीं हैं न? ठीक है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

प्रो. मनोज कुमार झा: महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री प्रदीप टम्टा (उत्तराखंड): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री सुशील कुमार गुप्ता: महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

डा. सस्मित पात्रा: महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

SHRI SHAMSHER SINGH DULLO (Punjab): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK: Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

Need for release of legacy loan of Rs.2,200 crore as a special package for Puducherry

SHRI N. GOKULAKRISHNAN (Puducherry): Mr. Chairman, Sir, the Union Budget for 2021-22 has dealt a deadly blow to the expectations of the people of the Union Territory of Puducherry. As compared to the last year grant of Rs.1,703 crores, the grant for the coming year is only Rs.1,729 crores. There is an increase of just 1.5 per cent. I had been repeatedly pleading in this august House that at least a 10 per cent increase should be given each year, considering the rising cost of prices and expenses. Already, there is a grouse in the minds of the people that the Central Government is treating the people of Puducherry with a step-motherly attitude.

MR. CHAIRMAN: No, no. Don't make allegations; make your suggestions. It has become a fashion.

SHRI N. GOKULAKRISHNAN: The Covid-19 pandemic impacted the finances of the UT very badly. It had to mop up the resources beyond the budgetary estimates. The Centre had to come to the rescue of all the States by arranging loans to manage the Covid-19 situation. That being so, an increase of a very meagre amount of Rs.26 crores over the previous year will not in any way help the Government to tide over the crisis. The demands for writing off the legacy loan of Rs,2,200 crores, a special package for having run the Panchayati Raj Institutions from 2011-16 and the reimbursement of the Pay Commission arrears are already pending with the Centre. In this situation, we expect the Centre to extend a helping hand by providing an instant increase in the allocation of budgetary grant at least by 10 per cent over the previous year grant.

Proposal to privatise the Rashtriya Ispat Nigam Limited

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Mr. Chairman, Sir, I thank you for having given me the opportunity. The foundation for the Visakhaptnam steel plant, that is, the Rashtriya Ispat Nigam Ltd. (RINL), was laid in 1977 by the then Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, after a prolonged agitation. The plant